on behalf of Shri Gajanand Sadashiv Potdar, claiming peusion on the basis of participation in the Delhi Conspiracy Case has since been sanctioned.

SCI Tanker Deal

*406. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a write up in the Economic Times of June 16,1993 under caption "SCI Tanker deal takes Shipping Circles by surprise";

(b) if so, what is the reaction of Govt, thereto: and

(c) whether Government have any plan to place order for tankers with the Hindustan Shipyard, Visakhapatnam to enable it to turn the corner?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir

(b) The report refers to placement of order by Shipping Corporation of India on South Korean Shipyards for acquisition of 4 Suezmax Oil Tankers at an estimated cost of US $ 65.53 Million each. The main point raised in the report is that it would have been advisable to go in for second hand Tankers taking into account the high price of new tankers. While considering the acquisition of the vessels, various factors are taken into account. These include the price of vessel, availability of finance, specific cargo requirement etc. Taking into account all these factors, it was felt that it would be better to go in for new acquisition rather than to acquire second hand tankers.

(c) Hindustan Shipyard can build ships upto about 50,000 tonnes only, whereas the crude oil Tankers are normally of the size of 80,000 tonnes and above. Thus Hindustan Shipyard is not equipped to build Tankers of the size required by the Shipping Corporation of India.

भारत और बंगलादेश के मध्य विवादास्पद द्वीप

*407. डा॰ जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री॰ राम जेठमलानी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बंगलादेश के मध्य अनेक द्वीप अभी भी विवादास्पद स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने द्वीप हैं जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में हैं और उनका निराकरण किया जाना शेष है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्ष तीन बीघा द्वीप के हस्तांतरण के समय इन द्वीपों से संबंधित विवादों को भी हल करने का वचन दिया गया था ;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा गत वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) : (क) और (ख) भारत-बंगलादेश भू-सिमा करार, 1974 के अनुसार बंगलादेश में भारतीय बस्तियों और भारत में बंगला-देशी बस्तियों का आदान-प्रदान किया जाना है । सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश में 130 भारतीय बस्तियां और भारत में 95 बंगलादेशी बस्तियां हैं ।

(ग) जी हां । सरकार भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार, 1974 से सम्बन्धित अनसुलझे मसलों को शीघ्र हल करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें बस्तियों के आदान-प्रदान का मसला भी शामिल है । 26 मार्च, 1993 को संसद में अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य में यह बात दोहराई गई थी कि सरकार 1974 के करार के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए वचनबद्ध है ।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में प्रयास किए जा रहे हैं कि इस मामले के क्रियान्वयन में शीघ्र प्रगति हो । इस विषय पर बंगला देश की सरकार के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता रहा है । 1974 के करार के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कानूनी तथा संवैधानिक कदमों की अन्य मंत्रालयों के परामर्श से विस्तार से जांच की गई है और इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता

*408. श्री राम जेठमलानी :
डा॰ जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कार्यरत हजारों स्वैच्छिक संस्थाओं को विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो देश में धर्म-प्रचार के लिये विदेशों से धन प्राप्त करती है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इन संस्थाओं को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और यह धनराशि कितनी थी जो केवल

धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही दी गई थी ;

(घ) क्या सरकार विदेशों से धनराशि प्राप्त करने की स्वतंत्रता के बावजूद निधियों के दुरूपयोग की संभावना को रोकने के लिये कानूनों में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण) : (क) से (ङ) 30-6-1993 को देश में कुल 14,683 एसोसिएशनें थी, जो विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकृत हैं । विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत, निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या समाजिक कार्यक्रम वाली एसोसिएशनें, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने के बाद, अथवा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकती हैं । धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्राप्त राशि में, धार्मिक स्थानों का निर्माण/विस्तार/रख-रखाव और मरम्मत, धार्मिक पुस्तकों इत्यादि का प्रकाशन, धर्म-प्रचारकों/पादरियों और धार्मिक समारोहों पर व्यय की जाने वाली राशि सम्मिलित है । 1990 में, एसोसिएशनों ने कुल 286.52 करोड़ रू॰ की राशि प्राप्त की है, जिन्होंने धार्मिक प्रयोजनों के लिए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना दी है । उसमें से 107.10 करोड़ रू॰ धार्मिक प्रयोजनों के लिए थे । जबकि 1991-92 के लिए प्राप्त सूचना अभी भी अन्तिम है, 341.51 करोड़ रू॰ की कुल राशि में से 140.35 करोड़ रू॰ की राशि धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्राप्त हुई । जहां तक 1992-93 की सूचना का संबंध है, विभिन्न संबंधित एसोसिएशनों से, मई, 1993 को प्राप्त होने वाली रिपोर्टें सभी एसोसिएशनों से प्राप्त नहीं हुई हैं । चूककर्ताओं को अनुस्मारक भेजे गए हैं ।

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है, ताकि उसकी खामियों को दूर किया जा सके । अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

कच्चे तेल का आयात

*409. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कमी होने के कारण इन उत्पादों का आयात करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में इतनी कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस के भूतपूर्व अध्यक्ष की क्या भूमिका रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में कूड के वास्तविक उत्पादन एवं उसकी मांग के मध्य हमेशा अन्तराल होता है, कुछ समय से कूड तथा उत्पादों की जितनी मात्रा में कमी होती है उसका आयात किया जाता है ।

(ख) गत वर्षों के दौरान देशी कच्चे तेल के उत्पादन में होने वाली कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :—

(1) बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र में किए जा रहे उपचारी उपाय ।

(2) गुजरात के कुछ क्षेत्रों में रिजर्वेयर संबंधी बाधाएं ।

(3) असम में कानून एवं व्यवस्था की समस्या ।

(ग) और (घ) अनेक नये तेल क्षेत्र विकास परियोजनाओं को स्वीकृत करने के अतिरिक्त, उत्पादन को अधिकतम करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि॰ द्वारा अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक उपाय किए गए हैं । देश में खोजे गए क्षेत्रों के विकास एवं तेल के अन्वेषण के लिए सरकार ने निजी भारतीय एवं विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया है ।

Increasing and Disturbing reports of pesticides destroying ozone layer

410. SHRI SOM PAL:

SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(4) whether Government are aware that there are increasing and disturbing reports of pesticides destroying ozone layer specially pesticides as reported in Food Commission, London of February, 1993 issue;

(b) whether any studies have been under-taken in the country on the subject and if so, the results thereof;

(c) whether the above pesticide will be banned;

(d) whether S. N. Banerjee Committee or any other Committee has recommended any action or alternative in the matter; and

(e) if so, what is the reaction of Government thereto?